



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक- 2916 /12-1 : देहरादून: दिनांक: 03 जून, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद-चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग हेतु 1.81 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/45735/2020)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या- 08बी/यू०सी०पी०/०६/७१/२०२१/एफ०सी०/१२७१, दिनांक २३.१२.२०२२

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक संख्या-3718/12-1 दिनांक 28.2.2025 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर द्वारा अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

क्र.सं.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर से प्राप्त आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। वन भूमि के विधिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
3 (क)	प्रतिपूरक वनीकरण- वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.62 हे० अवनत भूमि दशोली प्रथम क०सं० 3 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों तक का रखरखाव हेतु वन विभाग द्वारा आंकलित रू० 1476931.00 (चौदह लाख छयत्तर हजार नौ सौ इक्कतीस) मात्र की धनराशि RTGS SBI 52202306301532 दिनांक 20.06.2023 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.81 हे० वन भूमि के एवज में दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आरक्षित दशोली प्रथम क०सं० 3 पर 3.620 वन भूमि प्रस्तावित है। चालान की प्रति संलग्न है। संलग्नक-1
(ख)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्राप्त आख्यानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-2)

(ग)	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल सी0ए0 क्षेत्र, प्रस्तावित सी0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित चैकमेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिये कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	आख्यानसार उक्त सूचना को ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना एवं अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्रधिकरण वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
5 (क)	शुद्ध वर्तमान मूल्य इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में 1A नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0, दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.81 है0 वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मूल्य 1819340.00 लाठ लाख उन्नतीस हजार तीन सौ चालीस की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई है जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दरों पर एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-3)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 170 वृक्षों के साथ 62 sapling से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
7	गाईडलाईन में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों की कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि यह अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कोष	आख्यानसार प्रस्तावक विभाग द्वारा कैम्पा के खते में जमा की जा चुकी है को शर्त मान्य है। संलग्न-4

	प्रबन्ध और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। संलग्न-5
10	न्यूनतम वन संरक्षण नियम 28.6.2022 के अनुसार पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी धनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए, और परिपक्व वृक्षारोपण में वनस्पति धनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	आख्यानसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	आख्यानसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
12	नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौध रोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	आख्यानसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	आख्यानसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	आ आख्यानसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। संलग्न-6
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। संलग्न-7
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। संलग्न-8
17	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। संलग्न-9
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। संलग्न-10
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	आख्यानसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। संलग्न-11
20	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न। संलग्न-12
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न। संलग्न-13
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय	आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

	पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे ना गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी, एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षों की सूची पृथक से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। संलग्न-14
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुच्छेद आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	आख्यानसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित-2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2910 / 12-1/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बटनीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 3718

/ 12-1.

दिनांक, गोपेश्वर,

फरवरी 28 / 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/७१/२०२१/एफ०सी०/१२७१ दिनांक २३.१२.२०२३. 23.12.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर की पत्र सं० 110/23एल०ए०/23 एल०ए० दिनांक 13.01.2025 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है:-

क्र.सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में स्वीकृत वन भूमि में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.62 है० अवनत भूमि दशोली प्रथम क०स० 3 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यवहारिक हों स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। (ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र में पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (ग) प्रत्यावर्तित किये जाने के जाने वाले क्षेत्र की क०एम०एल०एम० फाईल, सी०ए० क्षेत्र, प्रस्तावित सी०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित चैक मेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों तक का रखरखाव हेतु वन विभाग द्वारा आंकलित रु० 1476931.00 (चौदह लाख छयत्तर हजार नौ सौ इक्कतीस) मात्र की धनराशि आर०टी०जी०एस०बी०आई०५५२२०२३०६३०१५३२ दिनांक 20.06.2023 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.81 है० वन भूमि के एवज में दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आरक्षित दशोली प्रथम क०स० 3 पर 3.62 वन भूमि प्रस्तावित है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्न-1) (ख) प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न-2)। (ग) उक्त सूचना को ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना एवं अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्रधिकारण वनीकरण 10 वर्षों तक अनुश्रुति किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
5	शर्त सं० 5 (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सचिव न्यायालय के WP (c) संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002 01.08.2003, 28.03.2008, 24.08.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी० (PT) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 -एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी दिनांक 05.02.2006 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.81 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध मूल्य अतिरिक्त राशि यदि जो अन्तिम रूप देने के बाद हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) शर्त सं० 05 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007/एफ०सी० दिनांक 02.05.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य 1819340.00 (अठारह लाख उन्नीस हजार तीन सौ चालीस) की धनराशि आर०टी०जी०एस०बी०आई०एन०-520230620562056301532 दिनांक 20.06.2023 वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (ख) वन भूमि के शुद्ध एन०पी०वी० वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो के राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूली जायेगा का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न-3)

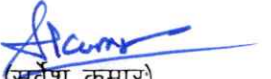
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पंजी० सं० 4389
पत्रावली 12-1
दिनांक 4-4-25

6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्तावित के अनुसार 170 वृक्षों के साथ 62 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के संज्ञित पर्यवेक्षण में करेंगे, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
7	गाईडलाइन में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों की कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कटाई से निगरानी करेगी। और यह सुनिश्चित करेगी कि यह तरह अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कोष प्रबन्ध और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा के खाते में ऑन पोर्टल के माध्यम से धनराशि जमा की जा चुकी है। (संलग्न-4)
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्न-5)
10	नवीनतम वन संरक्षण नियम 28.06.2022 के अनुसार पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए, और परिपक्व वृक्षारोपण में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	शर्त मान्य है।
12	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करे, कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौध रोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।	शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। (संलग्न-6)
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। (संलग्न-7)
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन की किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। (संलग्न-8)
17	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। (संलग्न-9)
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। (संलग्न-10)
19	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। (संलग्न-11)
20	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। (संलग्न-12)
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। (संलग्न-13)

22.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23.	प्रयोक्ता एजेन्सी पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाति के पौध लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी, एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षों की सूची पृथक से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। (संलग्न-14)
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी को जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
25.	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.nic/) पर अपलोड की जायेगी।	उक्त अनुपालन आख्या ई पोर्टल (https://parivesh.nic.nic/) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।
संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,


(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्राक:- 3718 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गेढवाल वृत्त उत्तराखण्ड चौड़ी को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर, को सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक - 110 / 23LA
सेवा में,

दिनांक - 13/01/2025

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :- जनपद चमाली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 है. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक 3202/23 एल०ए० दि० 17.10.2023।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्य हेतु गठित वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी०/यू०सी०पी०/06/71/2021/एफ०सी०/1271 दिनांक 23.12.2022 में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन इस कार्यालय के पत्रांक 3202/23 एल.ए. दि० 17.10.2023 द्वारा पूर्व में किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु कृपया पुनः बिन्दुवार अनुपालन आख्या गठित कर प्रेषित की जा रही है -

बिन्दु सं०	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में स्वीकृत वन भूमि में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नही किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण: (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्त अभिकरण की लागत पर 3.62 है. अवनत भूमि दशोली प्रथम क०सं० 3 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हों स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बंधे।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वन विभाग द्वारा आंकलित रु. 1476931.00(चौदह लाख छयत्तर हजार नौ सौ इक्कतीस) मात्र की धनराशि आर०टी०जी०एस०एस०बी०आई० 522023062056301532 दिनांक 20.06.2023 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.81 है. वन भूमि के एवज में दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आरक्षित दशोली प्रथम क०सं० 3 पर 3.620 है. वनभूमि प्रस्तावित है। चालान की प्रति सलग्न है। सलग्न 1 नं०।

[Signature]

(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। के0एम0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जायेगा। (ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0एम0 फाईल, सीए0 क्षेत्र, प्रस्तावित सी0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित केच मेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	(ख) उक्त सूचना वन विभाग के स्तर से सलंगन की जानी है। (ग) शर्त मान्य है।
4 प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि, आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकारण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	उपरोक्त बिन्दु सं० 3(क) के अनुसार।
5 शुद्ध वर्तमान मूल्य: (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 एवं 24.08.2008, एवं 9.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 030.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.81 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त	(क) शर्त संख्या 05 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 02.05.2022 तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य 1819340.00 (अठारह लाख उन्नीस हजार तीन सौ चालीस) की धनराशि आर०टी०जी०एस०बी०आई०एन०-5202306205 62056301532 दिनांक 20.06.2023 वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (ख) शर्त मान्य है, शपथ पत्र सलंगन है, नं (02)



	राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 170 वृक्षों एवं 62 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ों राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त मान्य है।
7	गाईडलाइन्स में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जायगी।	शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन ई-पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (संलग्न 3 नं०)
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	उपरोक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है (4-11)।
10	नवीनतम वन(संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature planttion) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होनी चाहिए।	शर्त मान्य है।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	शर्त मान्य है।

12	नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें, कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	उक्त बिन्दु में वन विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1896 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्त मान्य है। (सलंगन 11से 12)
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है। (सलंगन 12-13 है)
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनों स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा श्रमिकों हेतु वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था की जायेगी। (सलंगन 13-14 है)
17	संबन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। (सलंगन 14-15 है)
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में ही किया जायेगा। (सलंगन 15-16 है)
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य परियोजन हेतु नहीं किया जायेगा। (सलंगन 16-17 है)
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी। (सलंगन 17-18 है)
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। (सलंगन 18-19 है)

22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वादृष्टि स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह आनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना हेतु चिह्नित स्थलों पर मक डिस्पोजल किया जायेगा। (सलग्न 19-20 है)
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी। (सलग्न 20-21 है)

अतः अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रत्तर कार्यवाही कर इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।
सलग्न- अनुपालन आख्या चार प्रतियों में।

13.01.2025
अधिशायी अभियन्ता
प्रा.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता, लो.नि.वि., ज्योतिमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियन्ता
प्रा.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर**

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक 273/23 एल0ए0
सेवा में,

दिनांक 04/01/2023

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय- जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई-मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8 बी०/यू०सी०पी०/०६/७१/२०२१/एफ.सी./१२७१ दिनांक 23.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के पत्रांक 3151/12-1 गोपेश्वर दिनांक 28.12.2022 के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एन०पी०वी० की धनराशि का मांग इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिसके क्रम में क्षतिपूर्ति एन०पी०वी० की धनराशि की भुगतान हेतु मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

क्रम सं.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु मांग	एन०पी०वी० हेतु मांग	कुल
1	1476931.00	1819430.00	3296361.00

संलग्न:- मांग पत्र/ऑनलाईन चालान की छाया प्रति।

0/c

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

पत्रांक 273/23 एल०

दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता 7 वां वृत्त लो० नि० वि० गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

पप्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता (मुख्यालय) लो० नि० वि० गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

संलग्नक - 112

गोपेश्वर 103201
 GOPESHVAR 103201
 AGENCY COPY
 Phone : 01372-252172
 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
 आंध्र प्रदेश Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-06-2023

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6145735805
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/71/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	3296361/-

Amount in Words :Thirty-Two Lakh Ninety-Six Thousand Three Hundred and Sixty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896145735805 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through ch even after 7 working days, then kindly mail a copy c id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse ubin0903710@unionbankofindia.bank

SB INR 52023062056301532

अधिशाली अभियन्ता
 प्रान्तीय, खण्ड लो० नि० वि
 गोपेश्वर

Executive Engineer
 Provincial Division P.W.D.
 20 JUN 2023
 Monika Joshi

20 JUN 2023
 Soniya

- परियोजना का नाम— जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल 3.62 है० अवनत आरक्षित वन भूमि दशोली प्रथम क०स० 3 जो स्थल प्रस्तावित की गयी है। उक्त स्थल में पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।


प्रभगाय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वरा

प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.810 हे. वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

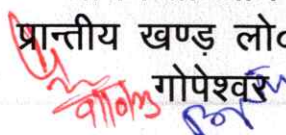
प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. धनराशि में बढोतरी होने पर अतिरिक्त धनराशि विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।


अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर
१०/१२

प्रमाण पत्र

यः— जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणार्ई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.810 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण उक्त धनराशि ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।


अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर


(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No-----

Dated-15/5/2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.810 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gopeshwar for Construction of Patalganga to Ganai-Molta Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Darhami, Nauligwad and Ganai villages in Joshimath tehsil. It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.810 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

जिला अधिकारी

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रभागीय कर्माधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० जि० वि०
गोपेश्वर

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mrs. Swati S. Bhadoria** I.A.S deputy commissioner **Chamoli** on dated 15.5.2020 at time 1.57.08 at 1.15..... in which application claiming rights in area measuring **1.810 hect** for the **Construction of Patalganga to Ganai-Molta Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Joshimath** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;

Dated: 15.5.2020


जिला अधिकारी
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee


प्रचिन कर्माधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली


अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

परियोजना का नाम-:जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 8 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पान मोटर सेतु निर्माण हेतु 1.810 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 4.900 किमी.।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम -गणाई, तहसील- जोशीमठ, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जोशीमठ परिक्षेत्र के पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 8 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पान मोटर सेतु निर्माण हेतु 1.810 हे. वन भूमि (सिविल सोयम 1.810 हे. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गणाई द्वारा दिनांक 08/12/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गणाई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर

[Signature]

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत
मुख्य अधिकारी
मुखर सहित
विकास खण्ड - जोशीमठ



सदस्य Ganaai

पं. गणाई-मोल्टा-पगनी
विकास खण्ड - जोशीमठ

[Signature]

दिनांक 19/12/2018

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुखर सहित



अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर



परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 3 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पान मोटर सेतु निर्माण हेतु 1.810 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 4.900 किमी.।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, जोशीमठ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, जोशीमठ

उपखण्ड जोशीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 8 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पान मोटर सेतु निर्माण हेतु 1.810 हे. वन भूमि (सिविल सोयम वन भूमि 1.810 हे.) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- जोशीमठ) की दिनांक 04-03-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री योगेन्द्र सिंह उपजिलाधिकारी ----- अध्यक्ष
- 2- श्री अनुराज कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी ----- सदस्य
- 3- श्री खजान सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी ----- सदस्य/सचिव
- 4- श्री दलवीर सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र ----- सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 8 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पान मोटर सेतु निर्माण परियोजना हेतु 1.810 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ----- द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जोशीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 8 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पान मोटर सेतु परियोजना के निर्माण हेतु 1.810 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जोशीमठ
जनपद चमोली।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

सदस्य
प. गणाई-मोल्टा-पगनी
उपखण्ड
बी०डी०सी०
सदस्य

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी महादय चमोली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जोशीमठ
जनपद चमोली।

ग्राम पंचायत का नाम:- राणाड़

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर



प्रपत्र - 23.1

दिनांक 08/12/18 को ग्रामसभा गढाई की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री कुन्दनसिंह फरस्वाण	कुन्दनसिंह
2	" अगतसिंह नेगी उपप्रधान गढाई	अगतसिंह
3	" बिजेन्द्रसिंह नेगी	बिजेन्द्रसिंह
4	" कुलदीपसिंह नेगी	कुलदीपसिंह
5	" कल्पेन्द्र प्रसाद भाजियाडी	कल्पेन्द्र
6	" दिनेशचन्द्र भाजियाडी	दिनेशचन्द्र
7	" जयदीपसिंह रावत	जयदीपसिंह
8	" मोहनसिंह	मोहनसिंह
9	" मुरलीसिंह	मुरलीसिंह
10	विक्रमसिंह रावत	विक्रमसिंह
11	मुनीषचन्द्र	मुनीषचन्द्र
12	सोहनसिंह	सोहनसिंह
13	आशोक	आशोक
14	राजेश्वर रावत	राजेश्वर
15	लक्ष्मी प्रसाद	लक्ष्मी प्रसाद
16	रमेश चन्द्र भाजियाडी	रमेश चन्द्र

DM FRA Letter

सदस्य G. V. S.
पं. गढाई-मोहवा-पगौ
विकास खण्ड - जोशीमठ

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर



गापेश्वर

प्रपत्र - 23.1

दिनांक 08/12/18 को ग्रामसभा अराई की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

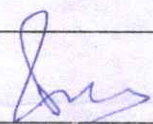
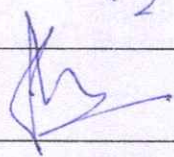
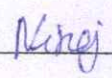
क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
17	श्री प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
18	श्री जगजित सिंह	जगजित सिंह
19	श्री लखन सिंह	लखन सिंह
20	श्री भरत सिंह	भरत सिंह
21	श्री रामू सिंह	रामू सिंह
22	श्री बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
23	श्री प्रताप प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
24	श्री जगत सिंह	जगत सिंह
25	नरेंद्र सिंह	नरेंद्र सिंह
26	धीरज पाण्डे	धीरज
27	सुखदेव सिंह	सुखदेव
28	रामगोपाल प्रसाद	रामगोपाल
29	दोस्त सिंह	दोस्त सिंह
30	संगीता देवी	संगीता देवी
31	आलू वारा सिंह	Alur Singh
32	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह

DM FRA Letter

अधिकासी अभियन्ता
प्रान्तीय खास ले. वि. वि.
गोपबन्धन

रादस्य अराई
ह.। पं. गणार्थ-मोल्दा-पानी
विहारा जगु - गोपीभट



क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
33	प्रेम सिंह	
34	दरमान सिंह	
35	तार प्रसाद	तार 5
36	दिलवर सिंह	
37	नीरज सिंह	
38	जयानन्द मजिपडी	जयानन्द मजिपडी
39	भरत सिंह	भरत सिंह
40	राजेश्वर सिंह	राजेश्वर सिंह
41	प्रभात सिंह पवार	
42	विमला देवी	विमला देवी
43	अमर सिंह	अमर सिंह
44	दिवाकर प्रसाद	दिवाकर
45	बट्टी प्रसाद	बट्टी प्रसाद
46	बशीर मजिपडी	बशीर मजिपडी
47	सीता देवी	सीता देवी
48	शंकर सिंह	Shankar Singh

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० वि० वि०
गोपेश्वर

सदस्य ०२०१४
पं. - गजानन मोहन पणौ
विकास खण्ड - जोशीमठ



प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

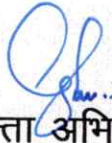
प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।


अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर
११/०३/२०२३

प्रमाण पत्र

विषय:— जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई-मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।


अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर


प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई-मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.810 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को वन विकास निगम से अथवा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा।


अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई-मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे. वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, वन भूमि सीमा को परियोजना लागत आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।


अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणार्ई-मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

गोपेश्वर
10/05/2017

प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणार्ई-मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे. वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

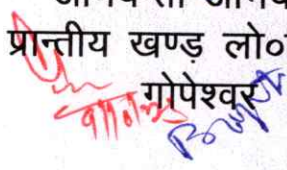
प्रमाणित किया जाता है कि, परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दृष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर
9/10/23

प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणार्ड-मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सी विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।


अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर


प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई-मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे. वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा


अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर
11/01/23

प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई-मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे. वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व विद्विष्ट स्थलों पर ही मलवा निस्तारण किया जायेगा।


अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर